को उक्त अधिनियम के सीमा क्षेत्र के अधीन लाया जा सके।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, जब कभी निर्धारित मजदूरी की अदायगी न किए जाने का मामला उनके ध्यान में लाया जाता है तो वे कार्रवाई करते हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षणों के फलस्वरूप कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने पर 35 अभियोजन मामले दायर किए गए हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने यह बताया है कि वर्ष 1989 में दो स्टील कंपनियों में हुई दुर्घटनाओं के कारण चार कर्मकारों की मृत्यु हुई। मृत कर्मकारों के पारिवारिक सदस्यों को दिए गए मुआवजे संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल सवारी डिब्बे का आरक्षण कराने संबंधी शुल्क

548. **श्री रजनी रंजन साहू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सामूहिक यात्रा हेतु रेल सवारी डिब्बे के आरक्षण के लिए ली जा रही अग्रिम धनराशि को कम करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलाकारों, खिलाड़ियों और समाजसेवियों को बिना बारी के मकानों का आवंटन

549. **श्री रजनी रंजन साहू:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कलाकारों, खिलाड़ियों और समाजसेवियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी के मकानों का आवंटन करने के संबंध में कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को एक वर्ष के दौरान आवंटित किये जाने वाले फ्लैटों की कुल संख्या का बिना बारी आधार पर अधिकतम $2^{1/2}$ प्रतिशत आवंटन, अति सहानुभूति और कठिनाई के मामलों में तथा ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों, शौर्य पुरस्कार प्राप्त रक्षा कार्मिकों व राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले अन्य व्यक्तियों को करने के लिये अधिकृत किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

शताब्दी एक्सप्रेस का चलाया जाना

550. **श्री रजनी रंजन साहू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में रेल की अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए सरकार के पास नई दिल्ली से पटना तथा पटना से नई दिल्ली तक शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Allocation of Funds for Construction of Dindigul-Madurai Railway Line in Tamil Nadu

551. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the allocation made for Dindigul-Madurai (Tamil Nadu) Broad gauge construction for the year 1989-90;

(b) what steps are taken to complete this work earlier; and

(c) by when construction work of broad gauge line between Madurai and Tuticorin (Tamil Nadu) taken up?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Rs. 4 crores.

(b) Within the limited allocation of funds made available by the Planning Commission for 'New Lines' and keeping in view the overall national priorities, efforts are made to allocate as much funds as possible for this project.

(c) Broad Gauge line between Maniyachchi and Milavittan has already been completed. Work on conversion of Madurai-Maniyachchi and Milavittan-Tuticorin Metre Gauge into Broad Gauge

will be taken up after the work on parallel Broad Gauge line between Dindigul and Madurai, at present in progress, is completed.

घाटे में चल रहे रेल मार्ग

552. **श्री राम नरेश यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कई रेल मार्ग हैं, जिन पर रेलवे को आर्थिक हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेल मार्गों की कुल संख्या कितनी है और क्या सरकार ने इन रेल मार्गों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और ये प्रयास कब और किन मार्गों के लिए किए गए थे?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) से (ग) रेल मार्गों के वित्तीय परिणामों का ऐसा कोई आकलन नहीं किया जाता है। तथापि, शाखा लाइनों के वित्तीय संचालन का अध्ययन हर वर्ष किया जाता है। 1987-88 के लिए किये गये इस प्रकार के अध्ययन के परिणामों के आधार पर 145 शाखा लाइनें अलाभप्रद पायी गयी थीं।

अलाभप्रद शाखा लाइनों की आमदनी बढ़ाने और संचालन व्यय को यथा संभव कम करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

1. ऐसी गाड़ियों को रद्द करना जिनमें बहुत कम संख्या में यात्री यात्रा करते हैं।

2. अलाभप्रद स्टेशनों/हाल्टों को बन्द करना अथवा उन्हें ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्ट में बदलना।

3. यात्री और माल गाड़ियों के स्थान पर मिश्रित गाड़ियां चलाना।

4. "केवल एक इंजन" प्रणाली लागू करना।

5. कर्मचारियों की संख्या में कटौती।

6. खंड पर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम।

"रेनफेड एग्रीकल्चर प्लान : स्टेट्स टोल्ड टू स्पीड अप प्रोपोजल्स" शीर्षक से समाचार

553. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1989 के "दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "रेनफेड एग्रीकल्चर प्लान: स्टेट्स टोल्ड टू स्पीड अप प्रोपोजल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार को अब तक ऐसे किन-किन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं जिनसे इस योजना के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): (क) और (ख) जी, हां। सभी 16 राज्यों ने 1989-90 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और वर्षा सिंचित खेती के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना कार्यान्वयन करने हेतु केन्द्रीय भागीदारी भी निर्मुक्त की गई है।

झुग्गी-झोपड़ी-निवासियों की सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

554. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निवर्तमान उपराज्यपाल ने माह जुलाई, 1989 में जीवन-यापन की बेहतर स्थिति के लिए दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों से सामूहिक आवास समितियां बनाने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण वर्ष 1983 में गठित की गई सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन नहीं कर पाया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों की सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटन करने के लिए कोई योजनाएं बनाई है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों के विकासार्थ धनराशि का कम उपयोग

555. **श्री राम जेठमलानी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गन्दी-बस्तियों के विकासार्थ धनराशि के कम उपयोग के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्लम फन्डस वेयर नोट यूज्ड फुल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रशासन दिल्ली की गन्दी